# पीएसयू बैंकों के लिए एक 'सुदर्शन चक्र' समाधान

साभार: लाइव मिंट
29 सितम्बर, 2017

मोंटेक सिंह अहलूवलिया
(अर्थशास्त्री)

**यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3 (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।**

हर कोई इस बात से सहमत है कि मौजूदा मंदी को पीछे छोड़ने और मध्यम अवधि में बेहतर विकास के लिए बैंकों को दुरुस्त करना कितना आवश्यक है। लेकिन एक विश्वसनीय समाधान अभी तक रेखांकित किया जाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर वीरिल आचार्य ने इस गंभीर समस्या की ओर सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि इंद्रधनुष, जिसकी घोषणा दो साल पहले की गयी थी, बैंकिंग सुधार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त नहीं है और हमें इसके साथ-साथ एक नए विकल्प 'सुदर्शन चक्र' की तलाश करनी होगी। कल्पना उचित है इंद्रधनुष भगवान इंद्र का हथियार नहीं है। यह 'इंद्रधनुष' केवल एक हिंदी शब्द है, जो एक अल्पकालीन घटना है, वैसे ही प्रकट होता है जैसे गायब हो जाता है। दूसरी ओर, सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु का हथियार हैं, जो एक बार आ जाये तो कुछ भी हो सिर काट कर ही प्रेषक के पास लौटता है।

तो अब हमें समझना है कि बैंकों की समस्या के लिए सुदर्शन चक्र क्या किरदार निभाएगा? हम इस आलेख में बैंकों से संबंधित चार 'आर' (R) पर विचार करेंगे, जिसे बैंकों की समस्याओं को हल करने की कुंजी कहा जाता है: मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार।

**पहचान :** यहां प्रगति है। भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता की समीक्षा से पता चला है कि सार्वजनिक और निजी दोनों बैंकों की कुल गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) का अनुपात पहले की तुलना में अधिक हो चुका है, लेकिन पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) बैंकों में, यह लगभग 12% हो गया। और यह एक अनुमान नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसी संपत्ति शामिल नहीं है, जो 'तनाव' हो, ये सिर्फ एनपीए हैं। बाजार का आकलन यह है कि समस्या इसी तरह कायम रहने पर एनपीए का प्रतिशत 6% तक और बढ़ सकता है।

**समस्या ऋण का संकल्प :** दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) भी कुछ सुदर्शन चक्र जैसे गुणों के साथ एक प्रमुख हथियार है। एक बार एक खाते को आईबीसी के तहत एक लेनदार द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के लिए भेजा जाता है और भर्ती कराया जाता है, प्रबंधन की शक्तियां और बोर्ड को एक स्वतंत्र दिवालिया पेशेवर (आईपी) में स्थानांतरित कर दिया जाता है। आईपी तब किसी के लिए उपयुक्त पद पर परियोजना को लेने के लिए तैयार है, जिसमें ऋण का अवलेखन शामिल है। ऋण का जरूरत की सीमा एक परियोजना से लेकर दूसरी परियोजना तक भिन्न होती है।

अगर आईपी एक निवेशक को ऋण की पर्याप्त कमी के साथ परियोजना को लेने के लिए तैयार है और लेनदार ऋण में कमी को स्वीकार करने में सफल होता है, तो नए प्रबंधन का कार्यभार अधिग्रहित हो जाता है। अगर कोई भी इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होता है या बैंक पैकेज द्वारा निहित ऋण को स्वीकार नहीं करता हैं, तो कंपनी का परिसमापन हो जाता है। कानून यह निर्धारित करता है कि प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक 90 दिनों तक बढ़ाई जानी चाहिए। यदि इस अवधि के भीतर कोई रिजॉल्यूशन नहीं है, तो परिसमापन होना चाहिए।

यह प्रक्रिया उन बैंकों के प्रबंधन के संबंध में प्रोत्साहित संरचना को बदलती है जो उचित दर कटौती का निर्धारण करने के लिए उन्हें एक कानूनी तौर पर विधि प्रदान करती है। चूंकि वैकल्पिक परिसमापन है, इसलिए वे किसी भी कटौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे उन्हें परिसमापन की तुलना में अधिक प्राप्त होगा। उम्मीद है कि यह प्रक्रिया केंद्रीय जांच ब्यूरो / केंद्रीय सतर्कता आयोग / नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में चिंता करने से प्रबंधन को मुक्त करेगी, जो भिन्न-भिन्न प्रकार से निर्णय लेने को हतोत्साहित करते हैं।

जून में, आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए कि वे 12 बड़े खातों के लिए दिवालियापन के आवेदन दर्ज करें जो कि भुगतान पर चूक गए थे। कानून द्वारा निर्धारित समय सारणी का तात्पर्य है कि इन खातों को हल किया जाना चाहिए या अप्रैल 2018 तक नवीनतम कंपनियों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। यह निश्चित नहीं है कि नए निवेशक इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो सकते हैं; इसलिए कुछ परिसमापन ठीक हो सकते हैं। यह प्रणाली के दृष्टिकोण से वास्तव में अच्छा है। आरबीआई ने 29 की पहचान की है, जिसे बैंकों को दिसंबर के मध्य तक 'हल' करने की कोशिश करनी चाहिए और इसके बाद दिवालिया याचिकाओं को फाइल कराना होगा यदि कोई रिजॉल्यूशन संभव नहीं होता है तो। यहाँ प्रश्न यह है कि क्या बैंक इन मामलों में से कुछ को हल करने में सक्षम हों पाएंगे? या क्या ये बातचीत प्रक्रिया के आधार पर मौजूदा प्रबंधन के पक्ष में बकाया ऋण को कम करने के लिए तैयार होंगे या नहीं? वे ऐसा करने के लिए अनिच्छा से डर के कारण उनको अयोग्य प्रबंधों का समर्थन करने के लिए आलोचना की जा सकती है। इस मामले में, अक्टूबर के आखिर में अक्टूबर, 2018 में अंतिम 29 दिसंबर तक आईबीसी रूट के नीचे आने वाले 29 मामले सामने आएंगे।

यह प्रक्रिया निश्चित रूप से अगले 12 महीनों में बैंकों हिसाब किताब को बेहतर बना देगी, लेकिन इसका मतलब यह भी कि बड़े नुकसान की स्वीकृति और पूंजी की इसी कमी होगी। यह निर्णय करना असंभव है कि नुकसान का स्तर क्या होगा। उदाहरण के लिए, सिनरजीज डूरे मोटर वाहन लिमिटेड मामला, जो IBC प्रक्रिया से उभरने वाला पहला था, यहाँ 94% के कटौती के साथ समाप्त हो गया। लेकिन यह एक पुराना मामला था, जिसे 2005 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड भेजा गया था। अब जो मामलों का उल्लेख किया जा रहा है, वह बेहतर हो सकता है, लेकिन फिर भी, बाजार की उम्मीदें हैं कि 60% या उससे अधिक की कटौती को आकर्षित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। इससे स्पष्ट रूप से पूंजी का काफी क्षरण हो जाएगा।

**पुनर्पूंजीकरण:** यह हमें तीसरा 'आर' पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। 2015 में, वित्त मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि पीएसयू बैंकों को 2.4 खरब डॉलर की पूंजी की आवश्यकता होगी, जिनमें से 1 लाख ट्रिलियन बाजार से आने वाला था, 60,000 करोड़ रुपये मुनाफे से और शेष 70,000 करोड़ रुपये बजट से। बजट प्रावधान विधिवत और मौजूदा इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत बनाया गया था, इस वर्ष और अगले वर्ष केवल 10,000 करोड़ रुपये की राशि कम है। यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त है क्योंकि एनपीए की स्थिति उम्मीद से ज्यादा खराब हो गई है।

फिच रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारतीय पीएसयू बैंकों को बेसल III के तहत पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मार्च 2019 के अंत तक 4 खरब डॉलर की पूंजी की आवश्यकता होगी। यदि फिच का अनुमान सही है, तो वित्त मंत्रालय के लिए यह एक बड़ी समस्या है। समस्या इस तथ्य से बिगड़ गई है कि वर्तमान मंदी का सामना करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए बजट पर दबाव है।

पीएसयू बैंकों को पुनर्पूंजीकरण करने के लिए सार्वजनिक निधियों का इस्तेमाल करने का दायरा केवल सरकार के खर्चों की कई अन्य मांगों के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जा सकता है। हम बजट के मुकाबले पीएसयू बैंकों की पूंजी की कितनी पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इसके स्पष्ट दृष्टिकोण के बिना, सरकारी खर्च में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करने की बात नहीं रख सकते।

**सुधार :** यह अंतिम 'आर' है, जो पीएसयू बैंकों में सुधार लाकर बैंकों को और अधिक कुशल बनाने की उम्मीद कायम रखता है। सुधार की आवश्यकता इसलिए स्वतंत्र है कि क्या सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल उनके पुनर्पूंजीकरण के लिए किया जा रहा है या नहीं। हालांकि, सुधारों को लागू करने के लिए बाध्यता अधिक है यदि बजट पर बोझ बढ़ता जा रहा है तो।

हमें किस प्रकार के सुधारों की जरूरत है? इनमें से कुछ को सुधार कहा जा रहा है, उदाहरण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विलय करने का विचार, सभी में सुधार नहीं है। बैलेंस शीट में सुधार करने के लिए अन्य बैंकों के साथ मजबूत बैंकों को मिलाने से कुछ भी नहीं होगा और विभिन्न बैंक कैडरों में समकक्षता स्थापित करने से संबंधित असंख्य कर्मियों की समस्याएं भी इसके इकाई का नेतृत्व करेंगे। हमें क्या सुधार लाने की जरूरत है। हमे प्रशासन को बेहतर बनाने, कौशल सेट अपग्रेड करने और पीएसयू बैंकों के भीतर जोखिम आकलन की गुणवत्ता में सुधार करने की जरूरत है।

सबसे महत्वपूर्ण सुधार चयनित पीएसयू बैंकों में सरकार की इक्विटी को 33% कम करना होगा। इससे मजबूत पीएसयू बैंकों को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिलेगी, जिसमें संभावित रणनीतिक निवेशक भी शामिल है, जिन्हें बोर्ड में सीटों की पेशकश की जा सकती है। बोर्ड पर प्रतिनिधित्व के साथ रणनीतिक निवेशकों को शामिल करने से बजट के बोझ के बिना पूंजी जुटाना आसान हो सकता है।

सरकारी इक्विटी को 33% कम करने का प्रस्ताव नया नहीं है। यह पहले 20 साल पहले 1998 में नरसिम्हन द्वितीय समिति द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वाजपेयी सरकार के वित्त मंत्री के रूप में यशवंत सिन्हा ने 1999 में ऐसा करने का ठान भी लिया था, लेकिन उस समय सरकार ने इसमें रुकावट डाल दी। आज भी कई दलों द्वारा इसका राजनीतिक विरोध किया जा सकता है, लेकिन वस्तु और सेवा कर के मामले में, आपको कभी भी यह नहीं पता कि सिस्टम कब सहमति के लिए तैयार है।

33% इक्विटी शेयर के साथ, सरकार को अभी भी बोर्ड में नियंत्रण की स्थिति कायम करनी होगी। बोर्ड, रणनीतिक निवेशकों के प्रतिनिधियों सहित सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेगा, खासकर नियुक्ति के संबंध में। शीर्ष प्रबंधन का वित्तीय सेवाओं के विभाग द्वारा ये बैंक अब माइक्रो प्रबंधन के अधीन नहीं होंगे। अंत में, यदि बजट दबाव में है, तो सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण देने में लक्षित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पुनर्पूंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। कमजोर बैंक जो अपनी पूंजी को बहुत कमजोर करते हैं, उन्हें आरबीआई की 'शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई' अनुशासन के अधीन होना चाहिए, जो कि उनकी पूंजी की स्थिति में सुधार होने तक नए व्यावसायिक ऋण को सीमित करता है। इससे निजी और सार्वजनिक दोनों बैंको को लाभ होगा। संक्षेप में, समस्या का स्तर सोचा था कि तुलना में बहुत बड़ा है और अर्थव्यवस्था में मंदी ने सुधारक उपायों की आवश्यकता भी जरूरी कर दी है। हमें सुधारों पर सुदर्शन चक्र की आवश्यकता है। केवल इंद्रधनुष से काम नहीं चल सकता।

## दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016

- दिवाला और दिवालियापन संहिता-2016 (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत डिफाल्ट के मामले में किसी बैंकिंग कंपनी को दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारम्भ करने संबंधी निर्देश के लिए आरबीआई के प्राधिकृत करने के लिए 04 मई, 2017 को बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2017 लागू किया गया है।
- यह अध्यादेश बाध्य होकर बेची जाने वाली परिसम्पत्तियों के मामले में निर्देश देने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को देता है। रिजर्व बैंक विवशतावश बेची जाने वाली परिसम्पत्तियों के बारे में बैंकिंग कंपनियों को सलाह के लिए बैंक की स्वीकृति के साथ समिति की नियुक्ति का निर्देश देने का अधिकार भी दिया है।
- रिजर्व बैंक के अंतर्गत आंतरिक निगरानी समिति (आईएसी) बनाई गई है। इस समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पांच कर दी गई है। पुनर्गठित निगरानी समिति को 500 करोड़ रूपये से अधिक उधारी के मामलों को सुलझाने के लिए समीक्षा का अधिकार है।
- भारतीय रिजर्व बैंक की आंतरिक सलाह समिति ने 5000 करोड़ रूपये से अधिक राशि वाले कोष गैर-कोषीय खातों की आईबीसी समीक्षा का सुझाव दिया। बैंकों द्वारा 31 मार्च, 2016 को 60% खातों को अनुत्पादक बताया गया है।
- इसी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक मानदण्डों के अंतर्गत आने वाले 12 खातों के मामले में दिवाला तथा दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत दिवाला प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। अन्य अनुत्पादक खातों, जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते, के बारे में आईएसी ने सिफारिश की है कि बैंक 6 महीने के अंदर इसके समाधान को अंतिम रूप दे। जिन मामलों का समाधान छह महीने के अंदर नहीं हो पाता, वैसे मामलों में बैंकों को दिवाला प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है।

## संभावित प्रश्न

**पीएसयू बैंकों में एनपीए की समस्या का स्तर हम सभी की सोच की तुलना में काफी बड़ा हो चुका है और भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी ने सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता को भी जरूरी बना दिया है। इस कथन के संदर्भ में सुदर्शन चक्र समाधान के महत्व के स्पष्ट करें।**

**The level of problem of NPA in PSU banks has become quite large compared to our thoughts and the recession in the Indian economy has made the reformative measures necessary. Explain Sudarshan Chakra solution in relation to this statement. (200 words)**